



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257125
CG-DL-E-13092024-257125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3584]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3584]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3919(अ).—यतः, मै. तेलंगाना राज्य इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड) ने जीनोम वैली, गाँव लालगडाई मलाकपेट, मंडल शमीरपेट, जिला रंगा रेड्डी, तेलंगाना राज्य (पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश) में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2636(अ) दिनांक 20.10.2009 और का.आ. 1324(अ) दिनांक 31.03.2016 द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 20.44 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था और बाद में 2.136 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित तथा 12.35 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. तेलंगाना राज्य इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड ने अब उपर्युक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के 10.226 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना राज्य सरकार ने पत्र संख्या 266/टीएसआईआईसी/प्रोजेक्ट्स/जीनोम/बायो एसईजेड/2009 दिनांक 17 मई, 2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से कल्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। अनधिसूचना के बाद, भूखंड राज्य सरकार की भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर योजनाओं के अनुसार होंगे;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र ने उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के 10.226 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा.सं. एफ.1/23/2009-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 3919(E).—Whereas, M/s. Telangana State Industrial Corporation Limited (formerly M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Bio-technology sector at Genome Valley, Village Lalgadai Malakped, Mandal Shameerpet, District Ranga Reddy, in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 20.44 hectares and later notified an additional area 2.136 hectares and de-notified an area of 12.35 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2636 (E) dated 20.10.2009 and S.O. 1324 (E) dated 31.03.2016, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Telangana State Industrial Corporation Limited has now proposed to de-notify the entire area of 10.226 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 266/TSIIC/PROJECTS/GENOME/BIO SEZ/2009 dated 17th May, 2021. After de-notification, the de-notified parcels would be utilized for industrial purpose and creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged. The land parcel after de-notification will conform to land use guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.226 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/23/2009-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.